नारायण भास्कर खरे

बनाम

भारत निर्वाचन आयोग

(और संबंधित याचिका)

(एस. आर. दास मुख्य न्यायाधीश, भगवती, जाफ़र इमाम, एस. के. दास, जे. एल. कपूर, गजेंद्रगड़कर और ए. के. सरकार, न्यायाधीशगण)

राष्ट्रपति, का चुनाव – ऐसे चुनाव से संबंधित संदेह और विवाद – सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्ति, कब प्रयोग किया जा सकता है – 'चुनाव', का अर्थ– भारत का संविधान, अनुच्छेद *71, 62* – राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, *1952 (1952* का *XXXI),* धारा *14*

याचिकाकर्ताओं ने 'भारत के पूरे क्षेत्र में आम चुनाव पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुनाव कराने के औचित्य पर गंभीर संदेह व्यक्त किया और, भारत के नागरिक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 71 (1) के तहत दायर आवेदनों द्वारा, अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। और ऐसे संदेहों की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में 6 मई, 1957 के लिए निर्धारित मतदान को केंद्र शासित प्रदेश में आम चुनाव होने तक रोकने का आदेश देने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के दो लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होना बाकी था, वह पूरा हो चुका है। तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण राष्ट्रपति चुनाव 12 मई, 1957 की आधी रात को होना था| याचिकाकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार थे और नामांकन पत्र प्राप्त करने की तारीख और इसे दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख के बीच का समय बहुत कम था, जिससे वह समय के भीतर इसे दाखिल कर सकें और दूसरे का मामला यह था कि वह पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार थे, जहां चुनाव होना बाकी था और उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोका जाएगा।

अभिनिर्धारित, कि वर्तमान याचिकाएँ समयपूर्व थीं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 71 (1) द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव से और उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्ति का उपयोग किसी विशेष उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 14 के तहत दायर एक चुनाव याचिका पर ही किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 71 में 'चुनाव' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसकी परिणति उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने में होती है और इस तरह के

चुनाव से उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों में इसके किसी विशेष चरण से संबंधित सभी संदेह और विवाद शामिल होने चाहिए।

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र, *(1952)* एस. सी. आर. *218,* संदर्भित।

यह चुनाव के कानून का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि सामान्य रूप से लोगों के हितों का अपमान करते हुए व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए चुनाव नहीं रोका जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 62, जिसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति का चुनाव उसके द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस तरह के हित में कल्पना की गई है, यह चरित्र में अनिवार्य है।

मूल क्षेत्राधिकार: 1957 की याचिका संख्या 63 और 64।

राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में संदेह के स्पष्टीकरण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 (1) के तहत याचिकाएँ।

आर. वी. एस. मणि और आई. आर. वी. शास्त्री, 1957 की याचिका संख्या 63 में याचिकाकर्ता के लिए।
आर . पटनायक, 1957 की याचिका संख्या 64 में याचिकाकर्ता के लिए।
एम. सी. सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी–जनरल, जी. एन. जोशी, पोरस ए. मेहता और आर. एच. ढेबर, दोनों याचिकाओं में प्रतिवादियों (कैविएटर्स) के लिए।

1957 मई 3. न्यायालय का फैसला दास मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया–

उपरोक्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 71 (1) के तहत और उसके तहत निहित अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग करने और इस संबंध में "गंभीर संदेह" के रूप में वर्णित की गई जांच और निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय का रुख किया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के साथ और चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह उक्त चुनाव के संबंध में मतदान को आगे न बढ़ाए, जो 6 मई, 1957 के लिए तय किया गया है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश सहित भारतीय संघ के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानमंडलों के सभी चुनावों को विधिवत पूरा करने के बाद। पहली मुख्य याचिका 26 अप्रैल, 1957 को और दूसरी 29 अप्रैल, 1957 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रत्येक याचिका के साथ एक नागरिक विविध याचिका भी दायर की गई है, जिसमें 6 मई 1957 को निर्धारित राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पर रोक लगाने की मांग की गई है। पहली मुख्य याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन दूसरी याचिका में उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है| विद्वान अटॉर्नी–जनरल चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए हैं और नोटिस की सेवा को माफ कर दिया है। इसलिए, हम अपने समक्ष मौजूद सभी याचिकाओं का निपटारा कर सकते हैं।

भौतिक तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है जिन्हें शीघ्र ही निम्नानुसार बताया जा सकता है:

भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनावों के बाद, हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, जहां से लोकसभा में चार सदस्यों की वापसी होनी है और पंजाब राज्य में दो निर्वाचन क्षेत्रों में, पुरानी लोकसभा को भंग कर दिया गया था। 4 अप्रैल, 1957 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का XLIII) की धारा 73 के तहत 5 अप्रैल, 1957 को नई लोकसभा का गठन किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (1952 का XXXI) की धारा 4 के अनुसार, चुनाव आयोग ने आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर नामांकन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल, 1957,

नामांकन की जांच की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, 1957, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, 1957, मतदान की तारीख 6 मई, 1957 और मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा की तारीख 10 मई, 1957 निर्धारित की। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 12 मई, 1957 की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाला है। उपरोक्त समय–सारिणी तय करने का कारण स्पष्ट रूप से यह था कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए।

7 अप्रैल, 1957 को नई लोकसभा के गठन की अधिसूचना प्रेस में प्रकाशित होने के बाद, पहली याचिका में याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र की आपूर्ति के लिए चुनाव आयोग को आवेदन किया, जो अंततः उसे 10 अप्रैल 1957 की दोपहर में नागपुर में प्राप्त हुआ। इससे नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पांच दिनों की अवधि बची। याचिकाकर्ता का कहना है कि समय बहुत कम था और समय की कमी के कारण उसे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। उन्होंने भारत के नागरिक और राष्ट्रपति चुनाव के लिए "इच्छुक उम्मीदवार" के रूप में याचिका दायर की है।

दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता हिंदू महासभा का सदस्य है और पंजाब राज्य के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने 28 जनवरी, 1957 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, क्योंकि मूल रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र में 24 फरवरी, 1957 को मतदान शुरू होना था। हालाँकि, मतदान स्थगित कर दिया गया और 2 जून, 1957 को निर्धारित किया गया। उन्होंने याचिका दायर की है भारत के नागरिक और लोकसभा के संभावित सदस्य के रूप में और उनका तर्क है कि यदि 6 मई, 1957 को राष्ट्रपति चुनाव होता है, तो वह संघ के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भेदभाव की शिकायत भी की है।

संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। उच्च पद के वर्तमान पदाधिकारी ने 12 मई, 1952 को अपने कार्यालय में प्रवेश किया, और, जैसा कि पहले ही कहा गया है, उनका कार्यकाल 12 मई, 1957 की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाला है। अनुच्छेद 62 (I) के लिए अनिवार्य रूप से चुनाव की आवश्यकता है राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। संविधान के इस स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, हमें अनुच्छेद 54 पर वापस जाना होगा, जो इस प्रकार चलता है: "54 राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल हैं–

(a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और
(b) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।"

एक तरफ यह कहा जाता है कि निर्वाचक मंडल में खंड (ए) और (बी) के तहत आने वाले वे सदस्य शामिल होते हैं, जो निर्णायक तिथि पर चुने जाते हैं, यानी वह तारीख जब चुनाव होना है। मान लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल संसद के कार्यकाल के दौरान समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 62(2) द्वारा विचार किए गए मामलों में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है और मान लीजिए कि संसद या एक या अधिक राज्यों के विधानमंडल में रिक्तियां हैं, तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 62(1) की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। रिक्तियां भरे जाने तक निवर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं रोका जा सकता। दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचक मंडल का गठन किया जाना चाहिए और इसमें दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होने चाहिए। चूँकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के दो निर्वाचन क्षेत्रों में बिल्कुल भी चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए निर्वाचक मंडल का गठन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे सदस्य भी निर्वाचित न हो जाएँ। यह बताया गया है कि यद्यपि वर्तमान अवसर पर हिमाचल प्रदेश के केवल

चार सदस्य और पंजाब राज्य के केवल दो सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं, फिर भी, यदि याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो सत्ता में कोई भी पार्टी भविष्य में व्यवस्था कर सकती है कई राज्यों में चुनाव स्थगित करके राष्ट्रपति के रूप में अपने स्वयं के नामांकित व्यक्ति के चुनाव के लिए, जहां उसे बहुमत सीटें मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि 28 मार्च, 1957 को तत्कालीन लोकसभा के कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि पूरे भारत में चुनाव संपन्न होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव कराना खतरे और अनुचित है। दोनों याचिकाकर्ता एक ही विचार साझा करते हैं और तर्क देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में एक "गंभीर संदेह" उत्पन्न हुआ है और अनुच्छेद 71 के तहत इस तरह के संदेह की जांच और निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किया गया चरम तर्क यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेह अच्छी तरह से स्थापित है या नहीं या यह अच्छा, बुरा या उदासीन है; जैसे ही कोई संदेह उत्पन्न होता है और कोई नागरिक उसके समाधान के लिए इसे इस न्यायालय के समक्ष लाता है, तो यह न्यायालय जांच करने और निर्णय लेने के लिए बाध्य है। इस मामले के प्रयोजन के लिए हमारे लिए संबंधित तर्कों के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन याचिकाओं का निपटारा एक संकीर्ण प्रारंभिक आधार पर किया जा सकता है।

अनुच्छेद 71 (1) निस्संदेह इस न्यायालय को "राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों" की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करता है और इस न्यायालय को जांच करनी होगी और निर्णय लेना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान में ऐसा कुछ है जो यह बताता हो कि ऐसे संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय किस समय और किस तरीके से किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और इस संविधान के तहत अभिनिर्धारित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण, जिसमें संसद और राज्यों के विधानमंडलों के चुनावों से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए चुनाव न्यायाधिकरणों की नियुक्ति शामिल है, जो चुनाव आयोग में निहित होंगे। यह देखा जाएगा कि समान शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात्, "चुनावों के संबंध में या उससे उत्पन्न संदेह और विवाद" जो कि अनुच्छेद 71 (1) में भी पाए जाते हैं। अनुच्छेद 327 द्वारा, संसद को संसद या राज्यों के विधानमंडलों के "चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में" सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत किया गया था। अनुच्छेद 329, अन्य बातों के अलावा, प्रावधान करता है कि इस संविधान में किसी भी बात के बावजूद, संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए किसी भी चुनाव पर ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा और इस तरह से कोई चुनाव नहीं किया जाएगा। उचित विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया। इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि चुनाव कैसे होंगे और कैसे और किन आधारों पर ऐसे चुनावों पर सवाल उठाया जा सकता है। इसने "ऐसे चुनावों के संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों" के निर्णय के लिए चुनाव न्यायाधिकरण नामक एक विशेष मंच भी स्थापित किया। एन पी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपीलकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया था। इसके बाद अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में निर्वाचन अधिकारी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने और निर्वाचन अधिकारी को प्रकाशित होने वाले वैध नामांकनों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और अपीलकर्ता इस न्यायालय में अपील लेकर आया। पूर्ण न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के पास रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अपील में मुख्य विवाद अनुच्छेद 329 (बी) में आने वाले शब्दों "चुनाव याचिका को छोड़कर किसी भी चुनाव पर

सवाल नहीं उठाया जाएगा" पर केंद्रित है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुच्छेद 329 (बी) में "चुनाव" शब्द को दिया जाने वाला अर्थ था। इस न्यायालय ने पृष्ठ 226 पर कहा:

"लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में लंबे समय तक उपयोग के कारण इस शब्द ने व्यापक और संकीर्ण दोनों अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। संकीर्ण अर्थ में, इसका उपयोग किसी उम्मीदवार के अंतिम चयन के लिए किया जाता है जो कि शामिल हो सकता है जब मतदान होता है तो मतदान का परिणाम होता है या जब कोई मतदान नहीं होता है तो किसी विशेष उम्मीदवार को निर्विरोध लौटा दिया जाता है। व्यापक अर्थ में, इस शब्द का उपयोग उस पूरी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है।"

श्रीनिवासलु बनाम कुप्पुस्वामी और सत नारायण बनाम हनुमान प्रसाद के मामलों का जिक्र करने के बाद और हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, द्वितीय संस्करण, खंड 12, पृष्ठ 237 में एक अंश के आधार पर, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि "चुनाव" शब्द का उपयोग पूरी प्रक्रिया के संबंध में उचित रूप से किया जा सकता था और किया गया था जिसमें कई चरण शामिल थे और कई को अपनाया गया था जिनमें से कुछ कदम प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं और इसलिए, यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस तरह के आदेश पर सवाल उठाने का एकमात्र तरीका संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 में निर्धारित किया गया था, और यह केवल चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका द्वारा ही किया जा सकता है, जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बाद किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। ऐसी चुनाव याचिका दायर होने पर चुनाव न्यायाधिकरण "चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवादों" की जांच करने और निर्णय लेने के लिए उचित रूप से बाध्य होगा, भले ही संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में कोई भी चरण हो, जिससे "संदेह और विवाद संबंधित हों|" अब हम इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में अनुच्छेद 71 के निर्माण पर विचार करते हैं।

जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है कि अनुच्छेद 71 (1) इस न्यायालय को "राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में सभी संदेह और विवादों" की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति प्रदान करता है। सवाल यह है कि क्या इस अनुच्छेद में या संविधान के किसी अन्य भाग में या कहीं और कोई संकेत है कि ऐसी जांच कब होगी? सबसे पहले, अनुच्छेद 71 "राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव" की परिकल्पना करता है और ऐसे चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों की जांच का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "चुनाव" का क्या अर्थ है? यदि हम अनुच्छेद 71 (।) में आने वाले "चुनाव" शब्द को वही व्यापक अर्थ देते हैं, जिसमें पूरी चुनाव प्रक्रिया शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से ऐसे पूर्ण चुनाव के बाद जांच की जानी चाहिए, जैसे कि, किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद, जैसा भी मामला हो। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि आलोचनात्मक शब्द को यह स्वीकृत अर्थ क्यों न दिया जाए। दूसरे स्थान पर, अनुच्छेद 71 के खंड 3 के तहत, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के "चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े" किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। यहां भी शब्द अनुच्छेद 327 में प्रयुक्त शब्दों के समान हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया के किसी भी चरण से संबंधित या उससे जुड़े मामलों को कवर करने के लिए समान रूप से व्यापक हैं। अनुच्छेद 71 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनावों से संबंधित या उनसे संबंधित कुछ मामलों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (1952 का XXXI) अधिनियमित किया है। इस

अधिनियम के प्रावधानों पर एक नज़र डालने से यह संकेत मिलेगा कि संसद की दृष्टि में इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का समय पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद है। इस अधिनियम की धारा 14 के तहत, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 से मेल खाती है, कोई भी चुनाव, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव, उस अधिनियम के भाग III के प्रावधानों और अनुच्छेद 145 के तहत इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। धारा 18, जो लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार निर्धारित करती है, निम्नानुसार हैः

18. निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार:– यदि सर्वोच्च न्यायालय की राय है–

(क) कि चुनाव में रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव का अपराध निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा या निर्वाचित उम्मीदवार की मिलीभगत से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है; या

(ख) कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है–

(i) इस कारण से कि चुनाव में रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो न तो लौटा हुआ उम्मीदवार है और न ही उसकी मिलीभगत से काम करने वाला व्यक्ति है; या

(ii) अनुचित तरीके से वोट लेने या अस्वीकार करने से, या

(iii) संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का अनुपालन न करने से; या

(ग) किसी भी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है या सफल उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है; सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित कर देगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चुनाव में रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव के अपराधों का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV) के अध्याय IX–A में है।

अनुभाग की भाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी वोट को अनुचित रूप से स्वीकार करना या अस्वीकार करना, या संविधान या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश का अनुपालन न करना या अनुचित स्वीकृति या नामांकन पत्र की अस्वीकृति को चुनाव को चुनौती देने का आधार बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के किसी भी चरण से संबंधित सभी संदेह और विवादों को व्यापक अर्थों में चुनाव संपन्न होने के बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत एक चुनाव याचिका द्वारा निपटाया जाना है।

उपर्युक्त व्याख्या हमें संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप और अच्छी समझ के साथ प्रतीत होती है। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले संदेह या विवाद को पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने से पहले इस न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है तो संभवतः पूरे चुनाव को पांच साल की समाप्ति तक रोका जा सकता है। 'शब्द जिसमें अनुच्छेद 62 के अनिवार्य प्रावधानों का गैर–अनुपालन शामिल होगा। चुनाव कानून, भारतीय और अंग्रेजी का अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत यह है कि चुनाव नहीं होने चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत बयान देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह

लोगों के सामान्य हितों का हनन है, जिसके लिए आवश्यक है कि चुनाव समय–सारिणी के अनुसार कराए जाएं। इसलिए, यह अनुच्छेद 62 के प्रावधानों के अनुरूप भी है और अच्छी समझ के साथ भी कि अनुच्छेद 71 में प्रयुक्त "चुनाव" शब्द का अर्थ चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। संसद ने अनुच्छेद 71 का यही अर्थ समझा, जैसा कि राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 से स्पष्ट है। पुनः इस न्यायालय ने प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाए हैं और उन नियमों के अवलोकन से यह भी संकेत मिलेगा कि "राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों" को पूरे चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद, यानी किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए।

यह बताया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं को पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक इंतजार करने और फिर चुनाव याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें यह दिखाना होगा कि राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 18 के अनुसार चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह अतिरिक्त बोझ या कठिनाई, जो अनुच्छेद 71 द्वारा लगाए गए शर्तों के अनुसार नहीं है, याचिकाकर्ताओं पर डाली जानी चाहिए। इन याचिकाओं के निपटारे के उद्देश्यों के लिए धारा 18 की इस आवश्यकता की वैधता या अन्यथा के बारे में कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है और हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन धारा 18 द्वारा लाई गई कथित कठिनाई की दलील अनुच्छेद 71 के सही अर्थ और महत्व को नहीं बदल सकती है। हमारे निर्णय में अनुच्छेद 71 एक चुनाव को अभिनिर्धारित करता है और अनुच्छेद 71 में होने वाले "चुनाव" शब्द का अर्थ है पूरी चुनाव प्रक्रिया जो एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने में समाप्त होती है और इस तरह के पूर्ण चुनाव के किसी भी चरण से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे समय के साथ, अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होना चाहिए जिसे समग्र रूप से चुनाव कहा जाता है।

दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग ने 6 मई, 1957 को चुनाव तय करके कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को संसद की सदस्यता के अन्य विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और उनका आनंद लेने के उनके अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित कर दिया है। यह तर्क उत्तर में उनके तर्क के अंतिम अंत में आधे–अधूरे मन से उठाया गया था और इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। किसी भी स्थिति में उन्होंने कोई ठोस तर्क नहीं दिया जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को कानून के समान संरक्षण से कैसे वंचित किया गया है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने होते हैं और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तविक चुनाव कराने के लिए उन विशेष इलाकों से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग–अलग तिथियां तय करनी होती हैं जिनमें निर्वाचन क्षेत्र स्थित होते हैं। यह मानने के लिए कोई अच्छा आधार स्थापित नहीं किया गया है कि कोई भेदभाव हुआ है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध है। जहां तक संविधान के समान संरक्षण खंड के उल्लंघन में कथित भेदभाव, यदि कोई हो, की गणना राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई संदेह पैदा करने के लिए की जा सकती है, तो यह संविधान के उन प्रावधानों का गैर–अनुपालन होगा जो पूरे चुनाव के समापन के बाद, राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 18 के तहत, चुनाव को प्रश्नगत करने के लिए आधार बनाया जा सकता है या नहीं, जिसके बारे में हम इस स्तर पर कोई अंतिम राय बनाने की आवश्यकता नहीं है।

हम पार्टियों के बीच किसी भी विवाद के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन, उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि वर्तमान याचिकाएँ समय से पहले हैं और इस स्तर पर उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम 1957 की याचिका संख्या 63 और 64 को खारिज करते हैं। 1957 की सिविल विविध याचिका संख्या 563 और 564 भी खारिज कर दी जाएंगी।

याचिकाएं खारिज की गई|